हिन्दी पाक्षिक

सेमन्या कण्वघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-13 अंक-17 हरिद्वार, बुधवार, 15 जुलाई, 2026 मूल्य-दो रूपया मात्र पृष्ठ-8

जनता की सेवा ही सरकार का धर्म:मुख्यमंत्री

देहरादून ,संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि प्रशासन को स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के प्रथम चरण में प्रदेशभर में छह लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की तथा 60 हजार से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन एवं समर्पण के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार जनता के बीच पहुंचकर अपनी जवाबदेही निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सीमान्त गांवों को प्रथम गांव के रूप में पहचान दिलाये जाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त '21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा' का संकल्प आज विकास कार्यों के माध्यम से धरातल पर साकार हो रहा है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। पहली बार राज्य में जी-20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गई, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नया विस्तार मिला। उन्होंने बताया कि राज्य में 3.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जीएसटी संग्रह बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज हुई है तथा स्टार्टअप, पर्यटन और होमस्टे के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन की सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है और युवा अपने गांव लौटकर स्वरोजगार अपना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर देश में ऐतिहासिक पहल की है। साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर प्रदेश में अब तक 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। चमोली जनपद के विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जिले में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। बदरीनाथ धाम, माणा, नीति एवं आसपास के क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अंतर्गत व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी 155 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 63 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जो जनपद के विकास को नई दिशा देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे भविष्य में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से वर्ष 2024 से अब तक चमोली के 76 गंभीर मरीजों को समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाकर उनका जीवन बचाया गया है इसके साथ ही हजारों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली की 42 हजार से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है तथा 25 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 48 हजार से अधिक किसानों को 196 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। दीनदयाल होमस्टे योजना के अंतर्गत जिले में 872 नए होमस्टे स्थापित हुए हैं, जिससे हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने आमजन से 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध की जायेगी कठोरतम कार्यवाही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण अत्यंत गंभीर मामला है और सरकार इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

कांवड़ यात्रा में 6 फीट से ऊंची कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी पर रोक

हरिद्वार । कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। छह फीट से ऊंची सामान्य कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी पर रोक लगाई गई है। हथियार, रेट्रो साइलेंसर, ऊंची आवाज वाले डीजे और नशे की हालत में यात्रा पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ मेले की तैयारियों के बीच 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिवभक्तों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सामान्य कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और कांवड़ झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक ऊंचाई होने पर विद्युत लाइनों से टकराने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि पिछले कांवड़ मेले में करीब चार करोड़ कांवड़िये गंगाजल लेने हरिद्वार आए थे। इस बार अनुमान है कि चार करोड़ से भी ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार पहुंचेंगे। इसलिए पुलिस के लिए कांवड़ मेला बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार पुलिस ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे अपने साथ वैध पहचान पत्र आईडी अवश्य रखें। एसएसपी ने ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को चलती ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित स्थानों पर यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान आपसी विवाद, मारपीट या तनाव से बचने और पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हो सके।

30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा कांवड़ मेला

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्य वस्थित और सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सभी शिवभक्तों से अनुरोध है कि निर्धारित नियमों का पालन करें। सामान्य कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न रखें। त्रिशूल, भाला, बेसबॉल का डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर न आएं। रेट्रो साइलेंसर वाली बाइक लाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा और साथ ही ऊच्चे और तेज आवाज वाले डीजे पर भी प्रतिबद्ध रहेगा।

मनसा देवी मंदिर में चढ़ावे की पारदर्शिता के लिए बिना जेब वाले कुर्तो की शुरुआत, पुजारियों को वितरित किए गए कुर्ते

हरिद्वार ,संवाददाता। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नई व्यवस्था लागू कर दी है। बुधवार से मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों को बिना जेब वाले विशेष कुर्ते बांटे गए। अब पुजारी और कर्मचारियों को इन्हीं कुर्तों को पहनाना होगा। बुधवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब वाले विशेष कुर्ते वितरित किए। अब बिना जेब वाले कुर्ते पहनकर ही पुजारी मंदिर में रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने मंदिर में बिना जेब वाले कुर्ते की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाया गया है। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा कि हाल के दिनों में अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी और बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी घटनाओं के बाद देशभर के मंदिरों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके विरोधी भी उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की शंका को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी प्रकरण कारण पूरे सनातन धर्म और मंदिर व्यवस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। कई बार चोरी जैसी घटनाएं छोटे कर्मचारी करते हैं, लेकिन उंगली बड़े पदों पर बैठे लोगों और मंदिर प्रबंधन पर उठाई जाती है। इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर में सेवा देने वाले पुजारी और कर्मचारी बिना जेब वाले कुर्ते पहनेंगे, जिससे चढ़ावे को जेब में रखने जैसी आशंकाएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा कि मंदिरों की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। ट्रस्ट का प्रयास है कि मंदिर की प्रत्येक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी पुजारी और कर्मचारी चोरी करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। श्रद्धालुओं ने स्वागत किया: मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी ट्रस्ट के इस निर्णय का स्वागत किया। उनका कहना था कि यह पहल मंदिर प्रशासन की ईमानदारी को दर्शाती है। श्रद्धालुओं ने उम्मीद जताई कि अन्य बड़े धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर किसी प्रकार की शंका न रहे और लोगों का विश्वास धार्मिक संस्थाओं में और अधिक मजबूत हो। इंदौर से आए श्रद्धालु प्रमोद कुमार दूबे ने बताया कि देश में उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए लेकिन ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहली बार देखी है। निश्चित रूप से इस शुरुआत से श्रद्धालुओं के अंदर विश्वास बढ़ेगा.

तीन साल पुराने वीडियो से फिर गरमाई मनसा देवी मंदिर की दान व्यवस्था पर बहस

हरिद्वार । मनसा देवी मंदिर की दान व्यवस्था से जुड़ा करीब तीन साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल होने से पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। वीडियो में एक व्यक्ति कुर्ते की जेब में पैसे रखते दिखाई दे रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मंदिर के प्रमुख श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने वीडियो को पुराना और सुनियोजित तरीके से दोबारा वायरल किया गया बताया। उन्होंने कहा कि दान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पुजारियों और कर्मचारियों के नए कुर्तों में जेब नहीं रखी गई है। वीडियो में दिख रहे मंदिर प्रबंधक महेश दुबे ने भी वीडियो को अपना बताते हुए कहा कि यह करीब तीन वर्ष पुराना है और वीडियो को गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है।

सम्पादकीय

चिंता के पहलु

फिनटेक से संबंधित भारत के महत्त्वपूर्ण डेटा तक अमेरिकी कंपनियों की पैठ गहराती जा रही है। भारत के डिजिटल पेमेंट क्षेत्र पर वॉलमार्ट, गूगल, मेटा आदि जैसी विदेशी कंपनियों का लगभग पूरा नियंत्रण है। फिनटेक ऐप क्रेड में 90 करोड़ डॉलर के निवेश और क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को ह्वाट्सऐप का वैश्विक प्रमुख बनाने के मेटा के फैसले से उचित ही भारतवासियों में उपलब्धि बोध भरा है। शाह अब अनेक बड़े नामों में शामिल हो गए हैं, जो भारत से शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। यह भारत की तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिभा तराशने की उच्च क्षमता की एक मिसाल है। मगर इस चकमते सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी हर उपलब्धि इस हकीकत को बेनकाब करती है कि भारत प्रतिभाओं का लॉन्च पैड बनने से आगे नहीं बढ़ पाया है। स्वदेशी प्रतिभाएं भारत में स्टार्ट-अप्स के जरिए अपनी पहचान बनाती हैं, जिन्हें जल्द ही खासकर अमेरिकी कंपनियां खींच ले जाती हैं। नतीजतन, आज तक एक भी भारतीय ब्रांड अपनी अद्वितीय वैश्विक पहचान नहीं बना पाया है। क्रेड के सिलसिले में यह चिंताजनक पहलू भी उभरा है कि भारतीय फिनटेक में रणनीतिक निवेश के जरिए देश के महत्त्वपूर्ण डेटा तक अमेरिकी कंपनियों की पैठ गहराती जा रही है। भारत के डिजिटल पेमेंट क्षेत्र पर वॉलमार्ट, गूगल, मेटा आदि जैसी विदेशी कंपनियों का लगभग पूरा नियंत्रण है। 2018 में लॉन्च हुए क्रेड के आज लगभग एक करोड़ 70 लाख यूजर हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड, बीमा खरीदारी, यूपीआई पेमेंट, ऋण, निवेश आदि से जुड़े कार्य इस कार्ड से करते हैं। ये भारत के सबसे समृद्ध उपभोक्ता हैं, जिनका बेहद अहम डेटा क्रेड के पास है। आशंका पैदा हुई है कि भविष्य में इस कंपनी अपना निवेश बढ़ाकर मेटा इन सारे आंकड़ों की मालिक बन सकती है। गौरतलब है कि ह्वाट्सऐप का इस्तेमाल भी पेमेंट ऐप के रूप में होता है। यह डेटा मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एजेंट के लिए भी बड़े काम का साबित हो सकता है। भारत में चीन की तरह डेटा ट्रांसफर पर रोक की कारगर कानूनी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संप्रभु एआई या संप्रभु हाई टेक का विकास की बातें खोखली नजर आने लगती हैं। इसीलिए क्रेड और मेटा में बना संबंध चिंता के पहलुओं को भी उजागर कर गया है।

अनुसंधान परिवेश की कमजोरियां

क्या अपनी खास जरूरतों के मुताबिक एआई का संप्रभु सिस्टम एवं प्रतिमान विकसित करने की दिशा में भारत बढ़ रहा है? जियो का प्रस्तावित 'संप्रभु एआई बैकबॉन' क्या इस कमी को पूरा कर पाएगा? रिलायंस जियो ने भारत की संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) रीढ़ निर्मित करने का इरादा जताया है। कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने जियो के उपभोक्ताओं के लिए जियो कॉल-एजेंट और एआई संचालित माई-जियो ऐप लॉन्च करने की घोषणा भी की। रिलायंस साधन संपन्न कंपनी है। अतीत में उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लीक से हट कर नई पहल करने और उनमें बड़ी कामयाबियां हासिल करने में वह सफल रही है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए लाजिमी है कि उसके हर एलान से लोगों गहरी दिलचस्पी पैदा होती है। कॉल-एजेंट 'हे जियो' कहने भर से कॉल ट्रांसक्रिप्शन, सारांश, एक्शन आइटम, रिमाइंडर, मीटिंग नोट्स, राइड बुकिंग, फूड ऑर्डर, टेबल रिज़र्वेशन आदि जैसी सेवाएं देगा। इसका इस्तेमाल भारत की सभी भाषाओं में किया जा सकेगा। बहरहाल, यह कोई नई राह बनाने वाली बात नहीं है। यह पहल इस समझ के अनुरूप ही है कि भारत एआई यूजर्स के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर सकता है। असल मुद्दा यह है कि क्या अपनी खास जरूरतों के मुताबिक एआई का संप्रभु सिस्टम एवं प्रतिमान विकसित करने की दिशा में भारत बढ़ रहा है? जियो का प्रस्तावित 'संप्रभु एआई बैकबॉन' क्या इस कमी को पूरा कर पाएगा? रिलायंस ने जामनगर में स्थित डेटा सेंटर, कच्छ स्थित क्लीन एनर्जी हब, एनविडिया के जीबी-300 चिप आधारित जीपीयू के उत्पादन आदि की योजना के जरिए इस दिशा में महत्त्वपूर्ण दावा किया है। लेकिन कंपनी यह दावा तभी पूरा कर सकेगी, अगर वह डेटा सेंटर के साथ-साथ एआई हार्डवेयर उत्पादन का भी स्वदेशी ढांचा खड़ा करे। एनवीडिया के चिप संप्रभु होने की गुंजाइश नहीं देते। उन पर अमेरिकी सरकार का नियंत्रण बना रहता है, जैसाकि चीन के मामले में जाहिर हुआ था। फिर रिलायंस की अमेरिकी कंपनी मेटा के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी है। अब तक रिलायंस हार्डवेयर और सॉफ्टेवेयर के मामले बाहर से आयात और मोटे तौर पर अमेरिकी प्रतिमानों पर निर्भर रही है। देश में तकनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान परिवेश की कमजोरियां भी इसकी एक बड़ी वजह हैं। क्या अब अपने बड़े इरादे के बूते रिलायंस इनसे उबर पाएगी, यह अहम सवाल है?

स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार के कीड़े

मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में मिड डे मील योजना (मध्याह्न भोजन योजना) की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में की गई थी। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' कर दिया है।योजना के मुख्य उद्देश्यइस योजना को लागू करने के पीछे निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ग्रामीण और वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाना। स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और बीच में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।कुपोषण से पीड़ित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाना।भूखे बच्चों की भूख मिटाकर कक्षा की गतिविधियों और पढ़ाई में उनका ध्यान केंद्रित करने में मदद करना।विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठाकर भोजन कराना, जिससे सामाजिक दूरी कम हो और भाईचारा बढ़े।

गरीब बच्चों को पोषण देने और स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए मिड-डे मील योजना भोजन पकाने में लापरवाही तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी के चलते योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, अनहाइजनिक और असुरक्षित भोजन खा कर बच्चे बीमार हो रहे हैं।कहीं मिड-डे मील मेन्यू के हिसाब से नहीं बनता तो कई बार भोजन में सुरसरी घुन कीड़े, कंकड़ छिपकलियां, मेंढक और यहां तक कि सांप मिलने की शिकायतें भी आती रहती हैं, हाल ही में एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह यह योजना लक्ष्य से भटक गयी है। आपको सुर्खियों में रही कुछ ताजा घटनाओं का हवाला देते हैं ताकि इस योजना के क्रियान्वयन में हो रही गड़बड़ी का अंदाजा लगा सकते हैं

1 जनवरी को 'ग्वालियर' (मध्य प्रदेश) के 'गोकुलपुर' गांव में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को परोसने के लिए बनाई गई आलू की सब्जी में मरा हुआ मेंढक निकला।

6 फरवरी को 'मधेपुरा' (बिहार) के 'साहूगढ़' स्थित सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में मिड-डे मील खाने वाले 70 से अधिक बच्चों को उल्टियां, पेट दर्द, घबराहट व बेचैनी होने लगी तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जांच करने पर सब्जी बनाने वाले बर्तन में मृत छिपकली पड़ी मिली।11 मार्च को 'कोयम्बटूर' (तमिलनाडु) के 'कबुंदमपयलम' गांव के सैकेंडरी स्कूल में परोसा गया मिड-डे मील खाते ही 44 छात्र फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि भोजन में एक छिपकली गिर गई थी।

14 अप्रैल को 'मयूरभंज' (ओडिशा) के एक सरकारी रैजीडैंशियल स्कूल में मिड-डे मील योजना के अंतर्गत पकाया गया दूषित भोजन करने से 100 से अधिक छात्र बीमार हो गए तथा पांचवीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई।

23 अप्रैल को 'मुंगेर' (बिहार) के 'सराधी' गांव के सरकारी सैकेंडरी स्कूल में मिड-डे मील में पकाए जाने वाले चावल के ड्रम में मरा हुआ चूहा और उसका मल-मूत्र मिलने से हड़कंप मच गया। 6 मई को 'अलवर' (राजस्थान) के 'नंगली' गांव के 'सीनियर सैकेंडरी स्कूल' के बच्चों को मिड-डे मील में परोसी गई दाल में मरा हुआ चूहा मिला। समय रहते पता चल जाने से यह दाल बच्चों को परोसी नहीं गई वर्ना कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। 8 मई को 'सीतापुर' (उत्तर प्रदेश) के 'तारनपुर' में स्थित 'सरकारी स्कूल' के मिड-डे मील में कीड़े निकले। 8 मई को ही 'सहरसा' (बिहार) के 'महिषी' कस्बे में स्थित सरकारी स्कूल में परोसा गया मिड-डे मील खाने के फौरन बाद 250 से अधिक बच्चे उल्टी, तेज पेट दर्द और घबराहट की शिकायत करने लगे जिस पर बच्चों को तुरंत इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया गया। बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि मिड-डे मील में सांप था।

30 जून को 'खगड़िया' (बिहार) में स्थित एक सरकारी स्कूल में कीड़ों वाला और खराब मिड-डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

और अब 3 जुलाई को 'दिल्ली' में 'हरीनगर' के एक सरकारी स्कूल के अपर प्राइमरी विंग के बच्चों को खाना बांटे जाने के दौरान एक हैल्पर ने मिड-डे मील के एक कंटेनर के अंदर मरी हुई छिपकली देखी। उसने तुरंत प्रशासन को सूचित किया और स्कूल प्रशासन ने तुरंत भोजन का वितरण रुकवाया।

हालांकि बच्चों को परोसने से पहले भोजन को एक अध्यापक सहित 2 वयस्कों द्वारा खा कर जांचना और कच्चे सामान व बर्तनों आदि की शुद्धता के नियमों का पालन करना जरूरी है परन्तु अधिकांश मामलों में इन नियमों का पालन ही नहीं किया जाता।

अत: मिड-डे मील बनाकर सप्लाई करने वाली संस्थाओं की निगरानी बढ़ाने और अपने यहां मिड-डे मील तैयार करने वाले स्कूलों के किचन और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने तथा सुरक्षित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने और उसके साथ ही घटिया खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस के संबंध में पता चला है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व नाम मिड डे मील) योजना के तहत भारत सरकार प्रति बच्चा (कुकिंग कॉस्ट/सामग्री) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए प्रतिदिन 6.78 और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए 10.17 देती है। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है।इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम (प्राथमिक) और 150 ग्राम (उच्च प्राथमिक) के हिसाब से मुफ्त अनाज (चावल/गेहूं) भी उपलब्ध कराया जाता है।विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कुल कुकिंग लागत का विवरण इस प्रकार है:बाल वाटिका और प्राथमिक स्कूल: ?6.78 प्रतिदिनअपर प्राइमरी स्कूल: ?10.17 प्रतिदिनवित्तपोषण यह कुकिंग लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात (सामान्य राज्यों के लिए) में साझा की जाती है। इसके अलावा, अनाज की पूरी लागत और उसे स्कूल तक पहुंचाने का खर्च 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कुछ राज्य अपनी ओर से इसमें अतिरिक्त धनराशि भी जोड़ते हैं।बच्चों के मिड डे मील की राशि भी सरकारी मशीनरी के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और पर्याप्त निगरानी के अभाव में कुछ एनजीओ मिड डे मील की राशि का बड़ा हिस्सा डकार जाते हैं। सरकार को इस पूरी योजना का पुनरीक्षण करना चाहिए।

लालढांग छात्रावास में स्वच्छता पखवाड़ा, छात्रों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

हरिद्वार । नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, लालढांग में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व बताने के साथ ही स्वच्छता संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वार्डन ने विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, लालढांग में मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही छात्रावास को स्वच्छता संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। छात्रावास के वार्डन योगेश्वर कुमार ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है। मन, तन, घर और गांव की स्वच्छता से ही स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश का निर्माण संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया।बीपीसीएल के सुरक्षा अधिकारी नितिन मोरे ने विद्यार्थियों को वर्ष में कम से कम 100 घंटे, यानी प्रति सप्ताह दो घंटे श्रमदान करने का संकल्प दिलाया।बिक्री अधिकारी भावेश श्रीवास्तव ने स्वच्छता के सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम के दौरान बीपीसीएल की ओर से छात्रावास को डस्टबिन, झाड़ू, फिनाइल, हार्पिक, सैनिटाइजर, हैंडवॉश समेत अन्य स्वच्छता सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर बीपीसीएल के दानिश, सूरज, राजकुमार, दीपक तथा छात्रावास के आयुष, आकाश, गोपाल, आशीष, तेजस्वी, प्रमोद, दीपा, मीना, संतोषी सहित अन्य छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

कांवड़ मेले को लेकर व्यापारियों संग पुलिस की बैठक

हरिद्वार । आगामी कांवड़ मेला-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर कोतवाली में मंगलवार को व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, भीड़ प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव लिए। व्यापारियों ने भी मेले को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली ने व्यापारियों एवं संभ्रांत नागरिकों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों ने पिछले कांवड़ मेले में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस वर्ष भी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की।बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा के समय आने वाली संभावित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों से सुझाव लेने के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात संचालन और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में मौजूद व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।

हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के काम 20 जुलाई तक पूरे करें

हरिद्वार । कांवड़ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे प्रशासन ने हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, गुणवत्ता बनाए रखने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ हिल बाईपास, सप्तऋषि क्षेत्र, रोड़ी बेलवाला मैदान और नजीबाबाद हाईवे का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद सड़कों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को मेले से जुड़े सभी कार्य 25 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष कांवड़ मेले और महाकुंभ की तैयारियां साथ-साथ चल रही हैं। ऐसे में कुंभ मेला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएंगी।

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि चार करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संभावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की व्यापक योजना तैयार की गई है। कांवड़ पटरी मार्ग, हाईवे, पार्किंग स्थलों और प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। आधुनिक निगरानी प्रणाली के जरिए यातायात संचालन सुचारु रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

हरिद्वार को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर मंथन, पुनर्वास और रोजगार पर रहेगा फोकस

हरिद्वार ,संवाददाता । हरिद्वार को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के सर्वे, पुनर्वास, कौशल विकास, रोजगार, जन-जागरूकता और विभिन्न विभागों के समन्वय को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन और आजीविका से जोड़ने के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऐसा शहर बने, जहां कोई भी व्यक्ति मजबूरी में भीख मांगने को विवश विवश न हो। इसके लिए मंदिरों, घाटों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में उनकी आयु, स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा और आजीविका संबंधी जानकारी जुटाकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की अलग-अलग श्रेणियां तैयार की जाएंगी।

बैठक में अस्थायी एवं स्थायी आश्रय गृह, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पुनर्वासित लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्थानीय उद्योगों, होटलों, दुकानों और सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने तथा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत भीख मांगने वाले बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, पोषण और आवासीय शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाल श्रम एवं बाल तस्करी से जुड़े मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने जन-जागरूकता अभियान चलाने, प्रमुख स्थलों पर संदेश प्रदर्शित करने तथा सोशल मीडिया, रेडियो और स्थानीय समाचार माध्यमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के बजाय जरूरतमंद लोगों को पुनर्वास योजनाओं से जोड़ने में सहयोग की अपील की?

बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के साथ गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय मजबूत करने, विभागवार जिम्मेदारियां तय करने और नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार, सीओ सदर एसपी बलूनी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अमित कुमार चंद, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा, उप नगर आयुक्त श्याम सुंदर दास, उप नगर आयुक्त रुड़की अमरजीत कौर, एसीएमओ डॉ. कुंदन कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

भाजपा प्रकोष्ठों की कार्यशाला में संगठन विस्तार और जनसंपर्क पर मंथन

हरिद्वार ,संवाददाता । भाजपा के प्रदेश और जिला प्रकोष्ठों की संयुक्त कार्यशाला मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, सेवा गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा सामाजिक संवाद को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री (आपदा प्रबंधन) विनय रूहेला ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने बताया कि मानसून को देखते हुए नालों की सफाई, सड़कों और पुलों की मरम्मत, जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल और विद्युत व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जा रहा है।

प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि भाजपा के सभी प्रकोष्ठ संगठन की रीढ़ हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने संगठन विस्तार, सामाजिक सहभागिता, सेवा कार्यों और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाने पर जोर दिया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने की आवश्यकता बताई। जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने समन्वय के साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। संचालन डॉ. संदीप गौड़ ने किया। कार्यशाला में कार्यपद्धति, अनुशासन, संवाद कौशल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर भी मार्गदर्शन किया गया।

शैक्षणिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए आईआईटी रुड़की ने उच्च शिक्षा में नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के 10वें बैच का आयोजन किया

रूड़की ,संवाददाता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पहल मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 8-12 जुलाई के दौरान नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के 10वें बैच का सफल आयोजन किया। इस पाँच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों एवं शैक्षणिक प्रशासकों की नेतृत्व क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, संस्थागत उत्कृष्टता एवं प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में देशभर के लगभग 20 विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे शैक्षणिक नेतृत्व से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान तथा सहयोगात्मक अधिगम के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध हुआ। 20 विषयगत सत्रों से युक्त व्यापक पाठ्यक्रम में परिवर्तनकारी नेतृत्व, संस्थागत प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकसित भारत 2047, नवाचार एवं डिजाइन थिंकिंग, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, संगठनात्मक व्यवहार, प्रेरणा, टीम निर्माण तथा लैंगिक संवेदनशीलता जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।

इन सत्रों का संचालन प्रख्यात शिक्षाविदों, प्रशासकों, उद्योग विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ लोक अधिकारियों द्वारा किया गया, जिनमें प्रो. के. के. पंत, प्रो. प्रवीण कुमार, प्रो. नवीन के. नवानी, प्रो. मीनाक्षी रावत, डॉ. तुहीना मुखर्जी, डॉ. अरुण भारद्वाज, डॉ. हिताशी लोमाश, प्रो. एच. सी. पोखरियाल, प्रो. सोनल अत्रेया, प्रो. आर. प्रदीप कुमार, एयर कमोडोर अजय कुमार चैधरी तथा श्री सेंथिल अवूदाई कृष्णा राज, आईपीएस शामिल थे।

अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रतिभागियों ने देहरादून स्थित लेखक गाँव का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने डॉ. रमेश पोखरियाल श्निशंकश् एवं सुश्री विदुषी पोखरियाल के साथ संवाद किया। इस संवाद ने भविष्य के शैक्षणिक नेताओं के निर्माण में साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, नैतिक नेतृत्व तथा मूल्य-आधारित शिक्षा की भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में समूह गतिविधियों, डिजाइन थिंकिंग कार्यशालाओं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सत्रों, चिंतनपरक चर्चाओं एवं प्रतिभागी प्रस्तुतियों सहित सहभागी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया, जिससे सहयोग, आलोचनात्मक चिंतन एवं अंतर-संस्थागत अधिगम को बढ़ावा मिला। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए विशेषज्ञों एवं सहकर्मियों के साथ संवाद के अवसर की सराहना की। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के अनुभव-साझाकरण एवं समापन सत्र के साथ हुआ, जिसने नेतृत्व विकास, संस्थागत उत्कृष्टता तथा क्षमता निर्माण के प्रति आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया। जैसी पहलों के माध्यम से संस्थान विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप दूरदर्शी शैक्षणिक नेतृत्व को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। इस कार्यक्रम ने संस्थागत परिवर्तन, नवाचार को बढ़ावा देने तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध शैक्षणिक नेताओं के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया।

पेट्रोल में एथनाल : आख़िर ये माजरा क्या है ?

निर्मल रानी

भारत में इन दिनों पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किये जाने यानी ई 20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाले नुक़्सान को लेकर बहस छिड़ गयी है। इसके प्रयोग से देश भर से वाहनों के इंजन ख़राब होने की ख़बरें मीडिया में आने लगी हैं। ई20 उपभोक्ता अब न केवल इसकी शिकायतें करने लगे हैं बल्कि जगह जगह इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी होने लगे हैं। गत दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ई 20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया गया।और इससे वाहनों को होने वाले नुक़्सान को लेकर सरकार को अवगत कराया गया। भारत में हो रहे इसके विरोध व इसके इस्तेमाल से आ रही परेशानियों व वाहनों को हो रहे कथित नुक़्सान की ख़बरों के बीच पड़ोसी देश भूटान ने भी भारतीय तेल कंपनियों से एथनाल मिश्रित ई 20 पेट्रोल वहां न भेजने व केवल पूर्व में भेजा जा रहा केवल शुद्ध ङ्क्क00 जैसे पेट्रोल की आपूर्ति करने को कहा है। भूटान द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर भण्डारण के पुराने भूमिगत फ़्यूल टैंक में ई 20 पेट्रोल के भण्डारण की वजह से पानी के रिसाव का जोखिम है जिससे एथनाल मिश्रित ईंधन ख़राब हो सकता है। क्योंकि इथेनॉल की प्रवृति नमी को आकर्षित करने वाली होती है और वातावरण से नमी लेने पर ईंधन की गुणवत्ता घट सकती है और इंजन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाक़े में स्टोरेज और सप्लाई श्रृंखला को आधुनिक करना भी आवश्यक होगा, जिसमें तत्काल परिवर्तन करना जोखिमपूर्ण माना गया। भूटान द्वारा अपनी आपत्ति में पहाड़ी रास्तों में वाहन के परफ़ार्मेंस पर भी फ़र्क़ पड़ने का संदेह व्यक्त किया गया है। भारत में भी देश भर से गाड़ियों के ख़राब होने,गाड़ियों की पेट्रोल टंकी के गलने व ज़ंग लगने,माइलेज कम होने व इंजन के ख़राब होने तक की शिकायतें आने लगी हैं। और उधर इसी ई 20 पेट्रोल की आपूर्ति व खपत की आड़ में शुद्ध पेट्रोल यानी ङ्क्क00 का मूल्य 167 रूपये प्रति लीटर तक हो गया है। एथनाल के उपयोग से केवल गाड़ियां ही ख़राब नहीं हो रही हैं बल्कि इसके उत्पादन में भी पानी का भी बेतहशा दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे भविष्य में यह जलसंकट का कारण भी बन सकता है। ग़ौरतलब है कि एथनॉल का उत्पादन चावल ,मक्का और गन्ना आदि की फ़सलों से होता है। और इन सभी फ़सलों की पैदावार में बेतहाशा पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब इसी फ़सल से एथनॉल बनाया जाता है तो इसमें और भी ज़्यादा पानी ख़र्च होता है। मिसाल के तौर पर चावल से 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 10790 लीटर पानी ख़र्च होता है जबकि मक्का से 1 लीटर एथनॉल बनाने में क़रीब 4670 लीटर पानी की खपत होती है इसी तरह गन्ने से मात्र 1 लीटर एथनाल बनाने में तक़रीबन 3630 लीटर पानी लगता है। गोया पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की नीति देश के जल बचाने के अभियान के ठीक विरुद्ध जलसंकट खड़ा करने में भी सहायक हो सकती है। ज़रा सोचिये कि जब श्व20 पेट्रोल की आपूर्ति में जल का इतना इस्तेमाल होता है तो यदि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की इच्छानुसार पेट्रोल में 85 प्रतिशत मिश्रण कर श्व85 की आपूर्ति की योजना पर अमल किया गया तो भारत जैसे उस देश में पानी के अकाल को कैसे टाला जा सकेगा जहां के कई इलाक़ों में पहले ही पीने का पानी लोगों को मयस्सर नहीं है ? हालांकि अब ख़बर यह भी आ रही है कि भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब श्व25 पेट्रोल को लागू करने की योजना को फिलहाल टाल सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस ई25 बदलाव को जल्दबाज़ी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीक़े से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश में पेट्रोल में एथनाल के मिश्रण को लेकर कुछ ज़िम्मेदार लोगों के विरोधाभासी बयान भी सुनाई दे रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों में एथनाल के मिश्रण के प्रति अविश्वास व भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्ज़ीक्युटिव वाईस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने अपने एक इंटरव्यू में पहले तो यह स्वीकार किया था कि श्व20 पेट्रोल के इस्तेमाल से 'बेशक फ़्यूल एफ़िशिएंसी में कुछ कमी आती है। ' परन्तु बाद में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे परफ़ॉर्मेंस के मामले में 'बेहतरीन ईंधन' भी बता डाला। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बायोफ़्यूलस के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी ने भी स्वीकार किया था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों की माइलेज में 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने गत 30 जून को सर्वोच्च न्यायलय में एक सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया कि श्व-20 पेट्रोल का इस्तेमाल फ़िलहाल एक प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद तो लोगों में और भी आक्रोश फैल गया कि आख़िर प्रयोग के तौर पर उन्हें 'गिनी पिग' अर्थात प्रयोग किये जाने वाला जीव क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ़ से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से कही जा रही बातें ग़लत हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी एक तरह से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की बातों का समर्थन करते हुए इस बात पर नाराज़गी जताई कि '3.6 करोड़ भारतीय कार मालिकों पर इसतरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि अभी भारत में 10 में से 9 गाड़ियां श्व20 के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति आम सहमति के बिना और इसके होने वाले परिणामों को समझे बग़ैर लागू कर दी गई है । खड़गे ने यह भी कहा, 'हमारी गाड़ियों में इसे ज़बरदस्ती डालने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन बदलने की इस प्रक्रिया को 'प्रयोग' नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जब सरकार का अपना डेटा ही अभी तक तैयार नहीं है, तो नागरिकों को नुक़्सान साबित करने की चुनौती नहीं दी जा सकती । आम लोग 'गिनी पिग' नहीं हैं न ही हमारी सड़कें टेस्ट ट्रैक हैं और देश के उपभोक्ताओं की जेबें सरकार के ट्रायल का बजट नहीं हैं। खड़गे ने श्व20 को वापस लेने मांग करते हुये कहा कि सरकार पहले इसे प्रयोग के योग्य,स्वीकार्य व प्रमाणित ईंधन साबित करे, फिर इसे प्रयोग करने की नीति लागू करें।' निश्चित रूप से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण देश के वाहन धारकों के लिये फ़िलहाल एक समस्या बन गया है और सरकार द्वारा इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों व विशेषज्ञों व इस नीति के आलोचकों द्वारा उठाये जा रहे बिंदुओं के बीच देश समझ ही नहीं पा रहा है की आख़िर ये माजरा क्या है ?

इंडियाहैंडमेड: भारत की शिल्प विरासत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म

इंडियाहैंडमेड एक समर्पित डिजिटल मार्केटप्लेस है जो भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाता है। यह मंच कारीगरों और बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़ता है, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करते हुए बाजार तक पहुंच का विस्तार करता है। यह जीआई-टैग और ओडीओपी वस्तुओं सहित विविध हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिससे क्षेत्रीय शिल्प उत्पादों की विभिन्न स्थानों पर मौजूदगी बढ़ती है।

हस्तनिर्मित आजीविका के लिए एक डिजिटल इंडिया ब्रिज

भारत दुनिया की सबसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समावेशी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

भारत में वर्तमान में अनुमानित 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। इस कार्यबल में महिलाओं की काफी भागीदारी है। अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार महिलाएं हथकरघा बुनकरों में 71 प्रतिशत और कुल कारीगरों का 64 प्रतिशत हैं। यह मजबूत भागीदारी विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में रोजगार और सशक्तिकरण का समर्थन करने में इस क्षेत्र की भूमिका को दर्शाती है।

बड़ी संख्या में कारीगरों और बुनकरों के बल पर यह क्षेत्र भारत के उभरते बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे-जैसे वाणिज्य तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन पहुंच इन शिल्प समुदायों को बाजार में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर रही है। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से, पारंपरिक आजीविका तेजी से डिजिटल व्यापार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर रही है।

इंडियाहैंडमेड को 2023 में लॉन्च किया गया। यह इस विजन को एक समर्पित डिजिटल मार्केटप्लेस में बदल देता है। वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित, यह प्लेटफॉर्म हस्तनिर्मित उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाता है और विक्रेताओं के लिए बाजार के व्यापक अवसर के द्वार खोलता है।

भारत में इंडियाहैंडमेड प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं

इंडियाहैंडमेड विक्रेताओं, खरीदारों और शिल्प विरासत का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई सुविधाओं के एक सेट के माध्यम से परंपराओं को ऑनलाइन बाजार में लाता है:

विशेष ऑनलाइन मार्केटप्लेस: यह बुनकरों और कारीगरों को अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है।

खरीदारों की सीधी पहुंच: कारीगर और बुनकर सीधे खरीदारों से जुड़े हुए हैं, जिससे बिचौलियों को कम करने और उचित मुआवजे का समर्थन करने में मदद मिलती है। अधिक मौजूदगी: प्लेटफ़ॉर्म इंडियाहैंडमेड उत्पादों को व्यापक ग्राहक आधार पर प्रदर्शित करता है, जिससे विक्रेताओं के लिए बाजार के अवसर बढ़ते हैं। डिजिटल सशक्तिकरण: कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए डिजिटल उपकरण और मौजूदगी प्रदान की जाती है।

वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण: व्यापक बाजार पहुंच आजीविका को मजबूत करती है और आय के अवसरों का समर्थन करती है।

सांस्कृतिक संरक्षण: शिल्प-आधारित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला भारत की हस्तनिर्मित विरासत को दृश्यमान रखती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने में मदद करती है।

इंडियाहैंडमेड सबसे अलग कैसे

पोर्टल को विश्वास, पहुंच और विक्रेता सशक्तिकरण के आसपास डिज़ाइन किया गया है। यह एक सहज बाज़ार प्रदान करता है, जहां कारीगर और बुनकर खरीदारों तक पहुंच सकते हैं और खरीदार अधिक आत्मविश्वास के साथ हस्तनिर्मित उत्पादों की खोज कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म रोजमर्रा के हस्तनिर्मित उत्पादों और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शिल्प के लिए एक क्यूरेटेड डिजिटल स्पेस प्रदान करता है। यह परिधान, घर की सजावट, साज-सज्जा, पेंटिंग, फर्नीचर, धार्मिक वस्तुओं, स्टेशनरी, संगीत वाद्ययंत्र, आभूषण, बैग और जूते सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

यह जीआई-टैग और ओडीओपी उत्पादों जैसी विशेष उत्पाद श्रेणियों पर भी प्रकाश डालता है। यह मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शिल्प को अधिक मौजूदगी और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

जीआई-टैग किए गए उत्पाद

जीआई-टैग किए गए उत्पादों में एक भौगोलिक संकेत होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट क्षेत्र, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा से जोड़ता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के जीआई-टैग वाले उत्पाद जैसे ऐपन कला, शुद्ध पश्मीना शॉल, डोकरा सजावट और मुंडू उत्पाद प्रदान करता है।

ओडीओपी उत्पाद

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल संतुलित क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने के लिए प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद की पहचान करती है और उसे बढ़ावा देती है। इस प्लेटफॉर्म में तंगेल साड़ी, बनारसी सिल्क उत्पाद, इकत, तसर सिल्क साड़ी, चंदेरी सिल्क और टेराकोटा उत्पाद शामिल हैं।

विश्वास बनाना और विक्रेता की भागीदारी को आसान बनाना

बेहतर पहुंच, बेहतर आश्वासन: खरीदारों को मुफ्त शिपिंग, खरीद सुरक्षा, सुरक्षित भुगतान और खरीदार समर्थन प्रणाली के माध्यम से अधिक विश्वसनीय खरीदारी अनुभव से लाभ होता है।

उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग दें उद्योग समूह : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग' कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

देहरादून ,संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग' कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों, विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारियों, सीएसआर पार्टनर्स, उद्योग एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तीर्थ स्थलों पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए कॉरपोरेट समूहों द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में, सीएसआर के तौर पर दिए गए योगदान का महत्व भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में जन्म लेना का अवसर तो ईश्वर देता है, लेकिन हर कोई देवभूमि में कर्म कर अपना योगदान दे सकता है। इसलिए

सभी लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से समूह सीएसआर के तहत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में स्थापित अन्य समूहों से भी अपना सीएसआर उत्तराखंड में ही खर्च करने की अपील की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई औपचारिक बैठक नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साझा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए किए गए हैं। साथ ही देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों ने उत्तराखंड के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की है।

उत्तराखंड की विकास संबंधित चुनौतियां भिन्न

इस मौके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय और सीमांत प्रदेश है। यहां की पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस राज्य की विकास संबंधी चुनौतियाँ भी अन्य राज्यों से भिन्न हैं। यहां ज्यादा संसाधन और मेहनत खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हमारे लिए 'समग्र विकास' का अर्थ केवल सड़कें, भवन और आधारभूत संरचनाएँ खड़ी करना ही नहीं है बल्कि रोजगार सृजन, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसलिए राज्य को ऐसा विकास चाहिए जो पहाड़ों की संवेदनशीलता का सम्मान करे, साथ ही जंगलों और नदियों को भी सुरक्षित रखने के साथ ही युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में कॉरपोरेट जगत का अनुभव, संस्थागत क्षमता, आधुनिक प्रबंधन शैली और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

औद्योगिक विकास को समर्पित सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2023 में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का आयोजन किया, जिसमें राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसमें से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए जहां एक ओर सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है। वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और स्वास्थ्य नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर उद्योगों को एक बेहतरीन और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इन्हीं प्रयासों से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ-साथ, उत्तराखंड को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 'एचीवर्स' तथा स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर्स' की श्रेणी प्राप्त हुई है।

पारदर्शी नितियों का लाभ मिला उद्योगों को

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल तब तक नहीं बन सकता जब तक कि शासन में पारदर्शिता न हो। इसीलिए, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बीते वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। राज्य सरकार की पारदर्शिता का सीधा लाभ उद्यमियों को मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी अनावश्यक बाधा या भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने उद्यमी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट' के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट कुशलता और प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियां मिलकर एक ऐसी 'सस्टेनेबल इकोनॉमी' का निर्माण करेंगी, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव विनय शंकर पांडेय, एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार, अपर सचिव मनमोहन मैनाली शामिल हुए।

कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता : मेलाधिकारी

सड़क, पुल एवं घाट निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी, सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों को भी प्राथमिकता से कराया जाए

हरिद्वार ,संवाददाता। मेलाधिकारी सोनिका ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों से जुड़े विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति, निर्धारित समयसीमा, विभागवार प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शुक्रवार को मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मेलाधिकारी ने कुम्भ मेला-2027 से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से एवं उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं विभागीय समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक विभाग अपनी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करे कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण हों तथा किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्भ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता, आधारभूत संरचना और व्यवस्थागत क्षमता का भी परिचायक है। इसलिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें।

मेलाधिकारी ने सड़कों, पुलों एवं घाटों के निर्माण तथा उनके सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू), लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को पूर्ण कराया जाए। निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाय।।उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य किया जाना है, उन्हें तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। विद्युत, पेयजल एवं अन्य उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए इन कार्यों को शीघ्र पूरा करें। यदि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसे तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, जिससे उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके और परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित न हो। मेलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा नियमित अंतरविभागीय समीक्षा के माध्यम से समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में समन्वय के अभाव के कारण अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।उन्होंने मेला क्षेत्र तथा उससे जुड़े प्रमुख मार्गों के सौंदर्यीकरण कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला-2027 में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को स्वच्छ, आकर्षक, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रमुख प्रवेश मार्गों, चौराहों, घाटों, सार्वजनिक स्थलों एवं महत्वपूर्ण परिसरों का योजनाबद्ध ढंग से सौंदर्यीकरण कराया जाए। मेलाधिकारी ने सड़कों के किनारे व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं हरित विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों, संपर्क सड़कों तथा मेला क्षेत्र के आसपास उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण कराया जाए तथा उनके संरक्षण एवं नियमित रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

हरिद्वार में युवती से छेड़छाड़ में हरियाणा के पर्यटक को भीड़ ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल

हरिद्वार । हरिद्वार में मंगलवार देर रात बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय युवती से छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा से आए पर्यटकों की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। जानकारी के अनुसार, बाजार में देर रात जैसे ही युवती से छेड़छाड़ की बात सामने आई। मौके पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ ने हरियाणा के पर्यटकों की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में युवतियों और आरोपियों के बीच बहस भी हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती के साथ कथित अभद्रता को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। उधर, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर घटना की पड़ताल की जा रही है।

आलिया की अल्फा ने पकड़ी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार

आलिया भट्ट पिछले कुछ दिनों से अपनी अपकमिंग स्पाई-थ्रिलर फिल्म अल्फा को लेकर चर्चा में थीं, जो अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की इस महिला प्रधान फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ भी मुख्य भूमिका में हैं और इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिका में हैं। ये स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म अल्फा 3 जुलाई यानी इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद, फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई की और अब ये तेजी से रफ्तार पकड़ती दिख रही है। रिलीज के दूसरे दिन, यानी पहले शनिवार को इसने 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो पहले दिन की तुलना में 2 करोड़ अधिक है।

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर अल्फा को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन कुछ नकारात्मक वजहों से। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद इसे दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद ये मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन में सफल रही। सैकनिलक के अनुसार, फ़िल्म ने भारत में 9.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और अब दूसरे दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जिसके अनुसार फिल्म ने पहले दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.50 करोड़ हो गया है।

कम कमाई के बावजूद, अल्फा ने एक अहम रिकॉर्ड बनाया है। ओपनिंग डे पर 9.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, यह आलिया भट्ट के करियर की 10वीं सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया (9.02 करोड़ रुपये) की ओपनिंग डे की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने 10वें नंबर पर जगह हासिल की है, जबकि ब्रह्मास्त्र 37 करोड़ के साथ टॉप पर है। वहीं 21.6 करोड़ की ओपनिंग के साथ कलंक दूसरे नंबर पर, 19.4 करोड़ के साथ गली बॉय तीसरे नंबर पर, 13.1 करोड़ के साथ शानदार चौथे नंबर पर और 12.42 करोड़ के साथ 2 स्टेट्स पांचवे नंबर पर है। वहीं बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने पहले दिन 12.25 करोड़, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 11.1 करोड़, गंगूबाई काठियावाड़ी ने 10.5 करोड़ और उड़ता पंजाब ने पहले दिन 10.05 करोड़ का कलेक्शन किया था।

अल्फा की बात करें तो यशराज फिल्म्स की इस स्पाई थ्रिलर में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं। ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये वाईआरएफ की पहली महिला प्रधान स्पाई-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल ने विलेन की भूमिका निभाई है और आलिया और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में वॉर के कबीर यानी ऋतिक रोशन का भी कैमियो है, जिसकी झलक ट्रेलर में भी देखने को मिली थी। हाल ही में करण जौहर ने एक पोस्ट साझा करते हुए अल्फा और आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की और फिल्म को अपना समर्थन दिया। करीना कपूर खान भी इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं।

अन्नू कपूर की उत्तर दा पुत्तर का ट्रेलर आउट: अंधविश्वास पर कॉमेडी का अनोखा तड़का

दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने फिल्म उत्तर दा पुत्तर का आधिकारिक ट्रेलर लॉन्च किया। ट्रेलर दर्शकों को एक ऐसी अनोखी कॉमेडी-ड्रामा दुनिया की झलक देता है, जिसमें हास्य, भावनाएं और सामाजिक व्यंग्य का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म मनोरंजक अंदाज में वास्तुशास्त्र, अंधविश्वास और उन धारणाओं पर कटाक्ष करती है, जो अक्सर लोगों के रोज़मर्रा के फैसलों को प्रभावित करती हैं। ट्रेलर एक ऐसी मज़ेदार दुनिया की झलक पेश करता है, जहां विश्वास, किस्मत और मानवीय भावनाएं अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपस में टकराती नजर आती हैं। कॉमिक पलों और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर उत्तर दा पुत्तर यह दिखाने की कोशिश करती है कि खुशी और सफलता की तलाश में लोग किस तरह दिशाओं, मान्यताओं और धारणाओं में समाधान खोजने लगते हैं।

फिल्म में अन्नू कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति के किरदार में दिखाई देंगे, जिसकी जिंदगी उस समय अचानक बदलने लगती है जब उसे यकीन हो जाता है कि सही दिशा उसकी किस्मत बदल सकती है। इसके बाद उसकी यात्रा कई मज़ेदार घटनाओं और उलझनों से गुजरती है, जो हंसी, भावनाओं और रिश्तों से भरपूर मनोरंजन का सफर बन जाती है। फिल्म में रुखसार रहमान, बृजेन्द्र काला, पवन मल्होत्रा, इश्तियाक खान, जीवेषु अहलूवालिया, राजेंद्र सेठी, सुमित गुलाटी और नितिन अरोड़ा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो फिल्म की कहानी को और रंगीन बनाते हैं। प्रोमोडोम मोशन पिक्चर्स के बैनर तले संदीप कपूर और प्रिया कपूर द्वारा निर्मित उत्तर दा पुत्तर का लेखन और निर्देशन रविंदर सिवाच ने किया है, जबकि इसकी कहानी संदीप कपूर द्वारा लिखी गई है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्माता संदीप कपूर ने कहा, उत्तर दा पुत्तर के ट्रेलर लॉन्च के लिए मनोज बाजपेयी का साथ मिलना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। यह फिल्म एक सम्पूर्ण फैमिली एंटरटेनर है। कहानी के केंद्र में हास्य है, लेकिन इसके जरिए यह भी दिखाया गया है कि कई बार लोग अपनी मान्यताओं और धारणाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। हमने इस विचार को हल्के-फुल्के और मनोरंजक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। निर्देशक रविंदर सिवाच ने कहा, उत्तर दा पुत्तर एक ऐसी दुनिया को पेश करती है जो मजेदार, वास्तविक और यादगार किरदारों से भरी हुई है। ट्रेलर सिर्फ दर्शकों को फिल्म की एक छोटी सी झलक देता है, जबकि फिल्म में इससे कहीं ज्यादा ड्रामा, हास्य और भावनाएं देखने को मिलेंगी। फिल्म उत्तर दा पुत्तर 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दुल्हन जैसी सजीं शनाया कपूर, मानसून के दिनों में शेयर कीं तस्वीरें

अभिनेत्री शनाया कपूर ने मानसून के दिनों में सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वह दुल्हन जैसी लग रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक बेहतरीन कैप्शन लिखा है। उनकी तस्वीरों पर उनकी मां समेत कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं।

शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने लहंगा और टॉप पहना है। उन्होंने गहने पहने हैं। एक हाथ में भर कर चूड़ियां पहनी हैं। उनकी मांग का टीका उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है।

तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा बारिश के दिनों में धूप जैसी चमको। शनाया की तस्वीरों पर उनकी मां ने दिल और नजर वाला इमोजी कमेंट किया है, ताकि उन्हें नजर ना लगे। भावना पांडे ने उन्हें खूबसूरत लड़की कहा है। एक और यूजर ने लिखा आप बहुत ही सुंदर हैं।

शनाया कपूर को आखिरी बार फिल्म तू या मैं में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ आदर्श गौरव थे। बिजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी। शनाया 2025 में विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां में नजर आ चुकी हैं।

विक्रांत मैसी लेकर आ रहे मुसाफिर कैफे, सीरीज की रिलीज तारीख का हुआ ऐलान

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'होममेड स्टोरीज' के नाम की आधिकारिक एलान कर अपने रचनात्मक सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत की है. इसके साथ ही उन्होंने इस बैनर की पहली पेशकश 'मुसाफिर कैफे' का टीजर भी जारी किया और यह घोषणा की कि यह रोमांटिक ड्रामा 24 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा. इस एलान के साथ दर्शकों को पहली बार उन भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों की झलक मिली है, जिन्हें यह नया बैनर बड़े पर्दे और डिजिटल माध्यम पर लेकर आने का लक्ष्य रखता है. ऐसे समय में, जब भारतीय सिनेमा पर एक्शन, क्राइम थ्रिलर और भव्य मनोरंजक फिल्मों का दबदबा है, विक्रांत मैसी ने अलग राह चुनने का फैसला किया है. 'मुसाफिर कैफे' के माध्यम से वह रोमांस और मानवीय भावनाओं को फिर से केंद्र में ला रहे हैं. यह फिल्म इस विश्वास को मजबूत करती है कि सादगी और ईमानदारी से कही गई कहानियां सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं. विक्रांत मैसी ने अपने अभिनय करियर में हमेशा कंटेंट-आधारित फिल्मों को प्राथमिकता दी है और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का भरोसा जीता है. राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनका सफर सार्थक और संवेदनशील कहानियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. ऐसे में निर्माता के रूप में उनका यह नया कदम पूरी तरह स्वाभाविक और प्रेरणादायक माना जा रहा है. 'मुसाफिर कैफे' का शीर्षक अपने आप में अपनापन, यादों की गर्माहट और भावनाओं से भरे एक खूबसूरत सफर का एहसास कराता है । कर रहे हैं, बल्कि संवेदनशील, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए एक नई पहचान भी बना रहे हैं. ऐसे दौर में, जब बड़े पैमाने की कहानियां सिनेमा पर हावी हैं, र

स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये मेकअप रिमूविंग मिसटेक्स, जानें और बचें इनसे

मेकअप आज के समय में महिलाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका हैं। महिलाएं अपनी नेचुरल स्किन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं। मेकअप महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं के आत्मविश्वाश को भी बढ़ाने का काम करता है। हर महिला के लिए मेकअप को सही तरह से अप्लाई करना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है उसे रिमूव करना। मेकअप रिमूव करते समय महिलाएं अनजाने में कुछ आम गलतियां कर बैठती हैं जिसका खामियाजा उनकी त्वचा को भुगतना पड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही मेकअप रिमूविंग मिसटेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी त्वचा को डैमेज होने से बचा सकती हैं। आइये जानते हैं इन मिसटेक्स के बारे में...

केवल फेशियल वाइप्स का इस्तेमाल करना

एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद यकीनन आप मेकअप रिमूव करने में बहुत अधिक समय और मेहनत नष्ट नहीं करना चाहेंगी। हो सकता है कि आप इसे जल्दी रिमूव करने के लिए फेशियल या क्लींजिंग वाइप्स का इस्तेमाल करती हों। लेकिन यह पूरी तरह से आपके मेकअप को क्लीन नहीं करते। इतना ही नहीं, फेशियल वाइप्स के इस्तेमाल के कारण चेहरे के एक क्षेत्र से दूसरे हिस्से में गंदगी स्थानांतरित करने का जोखिम अधिक होता है। यदि आप अपने चेहरे को क्लींजर और पानी से धोना नहीं चाहती हैं तो ऐसे में मिसेलर वाटर का इस्तेमाल करें। यह बेहद प्रभावी तरीके से चेहरे से मेकअप को हटा देता है। इतना ही नहीं, आपको बाद में अपना चेहरा धोने की आवश्यकता नहीं है।

बहुत जोर से रब करना

कुछ महिलाएं आई मेकअप करते हुए काफी जल्दी में होती हैं और इसलिए वह मेकअप को क्लीन करने के लिए बहुत जोर से रब करती हैं। अगर आप भी ऐसा ही करती हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ध्यान रखें कि आंखों के आसपास की त्वचा बहुत ही डेलीकेट होती हैं। इसे आगे और पीछे रगड़ने से त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन टूट सकते हैं, जिससे आप आंखों में लकीरें और महीन रेखाएं आ सकती हैं। जिससे आप समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगेंगी। इतना ही नहीं, जब आप जोर से रब करके आईमेकअप रिमूव करती हैं, तो इससे आंखों में दर्द, जलन व रेडनेस आदि की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए अपने आई मेकअप को हटाते समय ज्यादा दबाव डालने से बचें।

सही प्रोडक्ट का करें इस्तेमाल

मेकअप रिमूव करने के लिए अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखकर किसी अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाईड्रेटिंग तत्वों से भरपूर मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट का प्रयोग करने को ही तवज्जो दें। इससे आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहेगी।

लिपस्टिक को लास्ट में क्लीन करना

आपको लिप मेकअप बाद में रिमूव करना चाहिए या नहीं, यह आपके लिप कलर पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने बोल्ड लिपस्टिक को अप्लाई किया है तो ऐसे में बाद में लिपस्टिक को क्लीन करने की भूल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो मेकअप रिमूव करते समय लिपस्टिक आपके फेस पर फैल जाएगी और आपका काम बढ़ जाएगा। इसलिए लिपस्टिक को पहले क्लीन करें।

इन्स्ट्रक्शन को नजरअंदाज करना

यूं तो अधिकतर मेकअप रिमूवर एक ही तरह से काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेकअप रिमूवर ऐसे होते हैं, जो एक अलग तरह से प्रभाव डालते हैं और इसलिए आपको पैकेजिंग पर लिखे इन्स्ट्रक्शन को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। मसलन, अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप का उपयोग कर रही हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के मेकअप रिमूवर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यदि आपका मेकअप रिमूवर बोतल में आता है, तो उपयोग करने से पहले उसे हिलाना ना भूलें और निर्देश पढ़ने के बाद ही इस्तेमाल करें।

होममेड मेकअप रिमूवर को कहें ना

वैसे तो होममेड मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल त्वचा के लिए कैमिकल फ्री होता है। मगर, कुछ महिलाएं जानकारी के अभाव में घर पर मेकअप रिमूवर बनाते समय त्वचा को सूट ना करने वाली चीजों को भी इसमें एड कर लेती हैं। जिससे त्वचा पर खुजली और जलन होने लगती है। साथ ही होममेड मेकअप रिमूवर से मेकअप उतारने के लिए त्वचा को काफी रगड़ना भी पड़ सकता है। जिससे स्किन ढीली होने लगती है।

आखिरी में फेस वॉश ना करना

यह तो हम सभी जानते हैं कि मेकअप क्लीन करने के लिए मार्केट में अलग मेकअप रिमूवर अवेलेबल हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप केवल मेकअप रिमूवर से ही पूरी तरह मेकअप को क्लीन कर सकती हैं। अगर आप लास्ट में फेस वॉश नहीं करतीं, तो इससे मेकअप के कुछ पार्टिकल्स व गंदगी आदि चेहरे पर रह जाती है, जो वास्तव में उसे डैमेज कर सकती है। इसलिए पहले मेकअप को रिमूव करें और फिर फेस वॉश करें। अगर संभव हो तो आप गर्म तौलिये से भाप लेने की भी कोशिश करें।

सुबह खाना जल्दी बनाने के लिए रात में ही करें यह काम

हम खाना बनाने की कितनी ही जल्दी क्यों न करें लेकिन अक्सर लेट हो ही जाते हैं। यह प्रॉब्लम तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप आपको ऑफिस या कॉलेज जाना हो। सुबह के समय जल्दी, टेस्टी और बिना थके बनाना किसी टास्क से कम नहीं है। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं कुछ कुकिंग टिप्स-

रात को सब्जियां काटकर रखें

रात को सब्जियां काटकर फ्रिज में रखी जा सकती हैं। ऐसा करने से आपका काफी समझ बच जाएगा। खासकर अगर आप मल्टीपल डिशेज बनाने वाले हैं, तो यह काम जरूर करें।

राजमा, चना और दाल भिगाकर रखें

राजमा, चना और दाल ऐसी चीजें हैं, जिन्हें पकने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है इसलिए आपको इसे भिगाकर रखना चाहिए। जिससे कि आपको कम से कम टाइम देना हो। इन्हें भिगाने से पौष्टिकता तो बढ़ती ही है। साथ ही जल्दी भी पक जाते हैं।

रात में किचन मैनेज करके सोएं

सुबह उठकर आप कम पैनिक होंगे, अगर रात में आप किचन को साफ करके सोएंगे, इससे आपकी काफी मेहनत बच जाएगी और आपको कोई भी सामान तलाशने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

रात को सोचकर सोएं कि क्या बनाना है

आप अगर सुबह उठकर सोचेंगे कि क्या बनाएं, तो ऐसा सोचने में ही काफी टाइम खराब हो जाएगा इसलिए अच्छा यही होगा कि घर के लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आप रात में ही डिसाइड कर लें कि आपको क्या बनाना है। इससे घर के मेंबर्स के मूड और आपका टाइम दोनों बच जाएगा।

कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद?

कच्चे अंकुरित अनाज को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये न केवल स्वाद में अच्छे होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अंकुरित अनाज में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कच्चे अंकुरित अनाज को खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।

पाचन के लिए है बेहतरीन- कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो मल त्याग को आसान बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज में मौजूद खास तत्व पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इन्हें खाने से पेट साफ रहता है और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है।

वजन को नियंत्रित करने में सहायक- अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी हो सकता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन कैलोरी में कम होते हैं। इसलिए इन्हें खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। इसके अलावा अंकुरित अनाज में मौजूद फाइबर चर्बी के अवशोषण को कम करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

दिल की सेहत को बढ़ावा- दिल की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखें। इसके लिए कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल की सेहत में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को स्वस्थ रखते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

घुंघराले बालों की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खे

आमतौर पर ज्यादातर महिलाएं अपने बालों को घुंघराले यानी कर्ली लुक देने की कोशिश करती हैं। जबकि कुछ महिलाओं के बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले होते हैं और उन्हें उलझाव, रूखापन और टूटने जैसी बालों की समस्याओं का काफी सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपने घुंघराले बालों के साथ इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इनसे छुटकारा दिलाने में ये पांच घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।

सेब का सिरका आएगा काम-सेब का सिरका एक प्राकृतिक हेयर क्लेरिफायर के रूप में काम करता है और आपके घुंघराले बालों को मुलायम बनाने के साथ चमक देता है। लाभ के लिए सेब के सिरके और पानी की बराबर मात्रा को मिला लें और फिर अपने बालों को अच्छी तरह से शैंपू करके इस घोल से अपने बालों को धो लें। इसके बाद अपने सिर को ठंडे पानी से फिर से धो लें। महीने में दो बार इस नुस्खे को दोहराएं।

अंडे का करें इस्तेमाल-अंडे प्रोटीन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो घुंघराले बालों का टूटना रोकने के साथ उन्हें मुलायम भी बना सकते हैं। लाभ के लिए एक कटोरे में एक अंडा फेंट लें। अब इसमें एक बड़ी चम्मच मेयोनीज और एक बड़ी चम्मच जैतून का तेल मिलाएं। इसके बाद इसे अपने बालों में लगाकर 30 मिनट के बाद सिर को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें। हफ्ते में एक बार इस प्रक्रिया को दोहराने से बड़ा लाभ मिलेगा।

बीयर है प्रभावी-बीयर घुंघराले बालों को आसानी से सुलझाने से लेकर इनके टूटने की संभावना कम होने जैसे कई लाभ मिल सकते हैं। लाभ के लिए सबसे पहले अपने बालों को शैंपू और पानी से धो लें। अब धीरे-धीरे अपने बालों पर बीयर डालें और इसे लगभग पांच मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सिर को फिर से ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करें। इससे बालों की चमक और बढ़ जाएगी।

एवोकाडो करेगा मदद-एवोकाडो में विटामिन- ई एक प्रमुख पोषक तत्व है। यह आपके घुंघराले बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ उन्हें चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक एवोकाडो को मैश करके इसके साथ दो बड़ी चम्मच दही मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं और लगभग एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

उच्च शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून ,संवाददाता । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

एआईसीटीई मानकों के अनुरूप पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के समुचित विकास के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम तथा आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित विश्वस्तरीय शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता, उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी

राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026' के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई।

राज्य भण्डारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के नियमित 68 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी लेखा परीक्षा के लिए दो पदों का सृजन

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित कुल दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और अधिक सशक्त

राज्य में वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन तथा दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे उत्तराखण्ड के युवा

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन हेतु सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण एवं नियोजन से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर कैबिनेट का मार्गदर्शन

ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं भावी कार्यवाही के संबंध में कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त

राज्य में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से 'अरेबिया मदरसों को अनुदान' संबंधी बजट मानक मद को समाप्त (विलोपित) किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे। कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ विकास एवं जनकल्याण के प्रयास और अधिक प्रभावी होंगे।

दो युवकों को सिडकुल में दबोचा

हरिद्वार । नवोदय नगर में चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे दो युवकों को सिडकुल पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से प्लास, हथौड़ा, छैनी और सरिया जैसे नकबजनी के औजार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई की रात गश्त के दौरान निर्माणाधीन थाना भवन के पास दोनों युवक संदिग्ध हालात में दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन पीछा कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान मोहित शुक्ला निवासी गांव मोहरनिया, थाना महोली, जिला सीतापुर हाल निवासी नवोदय नगर और यतेन्द्र कुमार निवासी भोगपुरी, थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर (हाल निवासी साई मंदिर के पास, सिडकुल के रूप में बताई। दोनों ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की योजना बनाने की बात कबूल की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

तीन गांव के 17 घरों में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी पकड़ी

हरिद्वार । ऊर्जा निगम ने जगजीतपुर क्षेत्र के तीन गांवों में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 17 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सभी के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ऊर्जा निगम ने बुधवार को जगजीतपुर सबडिवीजन के कटारपुर, फेरुपुर और इक्कड़ खुर्द गांव में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया और बिजली चोरी पकड़ी। अधिशासी अभियंता रवि कुमार के निर्देश पर एसडीओ अमित तोमर के नेतृत्व में चली कार्रवाई में घरेलू परिसरों की जांच की गई। जांच के दौरान बिजली चोरी की पुष्टि होने पर सभी के खिलाफ मौके पर आवश्यक कार्रवाई की गई। ऊर्जा निगम ने 17 आरोपियों पर जुर्माने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ संबंधित थाने में भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमे भी दर्ज करा दिए हैं। एसडीओ अमित तोमर ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अभियान में जेई वरुण प्रताप, जेई प्रीति जिंटा सहित ऊर्जा निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

नशा तस्करों पर सख्ती के निर्देश, स्कूलों और गांवों में चलेगा जागरूकता अभियान

हरिद्वार । नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित एनसीओआरडी (नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल) समिति की बैठक में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, संभावित अवैध लैब पर कड़ी नजर रखने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और जनजागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज कर हेरोइन (स्मैक), चरस, गांजा और प्रतिबंधित दवाओं सहित विभिन्न मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। अवैध तस्करी और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित संभावित क्लैंडेस्टाइन लैब की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक एवं अन्य प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए औषधि निरीक्षक नियमित निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान चलाएं। अपर जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत ग्राम पंचायतों, शहरी क्षेत्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि जनपद को नशा मुक्त बनाने के अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में एसपी ट्रैफिक निशा यादव, सीओ सदर संजय शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर दर्शन सिंह, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी दीपक कुमार, इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पुराना आरटीओ चौक से नगर सीमा तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

हरिद्वार । कांवड़ यात्रा और शहर में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को उत्तरी हरिद्वार में पुराना आरटीओ चौक से नगर सीमा तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 60 अतिक्रमण हटाए गए। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट हरगिरी के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान फ्लाईओवर के नीचे और सड़क किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 60 अस्थायी अतिक्रमण हटाए और मौके पर रखा सामान भी जब्त किया।

स्वामी,मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड़) से प्रकाशित किया।

सम्पादकः अवनीश कुमार, मो० 9410553400

ई-मेलः liveskgnews@gmail.com

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)

सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नही है।